



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 श्रावण 1948 (श0)  
(सं0 पटना 1003) पटना, सोमवार, 17 अगस्त 2026

सं० 4सं./प्र.2-04/2016 (खण्ड-2) 294/वि०  
कला एवं संस्कृति विभाग

संकल्प

13 अगस्त 2026

विषय:- भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम ज्ञान भारतम मिशन के अन्तर्गत सर्वेक्षित पाण्डुलिपियों के डिजिटलीकरण और मेटाडेटा निर्माण योजना की स्वीकृति एवं इस पर कुल राशि ₹ 6,23,68,718/- (छः करोड़ तेईस लाख अड़सठ हजार सात सौ अठारह रुपये) मात्र के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु राज्यादेश।

भारत सरकार द्वारा भारत की समृद्ध ज्ञान परम्परा और बौद्धिक विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में फ्लैगशीप पहल के रूप में “ज्ञान भारतम मिशन” की घोषणा की गई है। इस मिशन के अन्तर्गत देश भर में उपलब्ध भारतीय ज्ञान परम्परा से जुड़ी पाण्डुलिपियों के वैज्ञानिक सर्वेक्षण, डिजिटिजेशन एवं अभिलेखीकरण किया जा रहा है, ताकि यह अमूल्य धरोहर शोधार्थियों/विद्यार्थियों और आम नागरिकों के लिए सुलभ हो सके।

- ज्ञान भारतम मिशन के प्रथम चरण में पाण्डुलिपियों के सर्वेक्षण हेतु दिनांक 16.03.2026 से राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वे प्रारम्भ हुआ है। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध-सरकारी पत्र संख्या-GBM/42/2026-25 (E-78817), दिनांक-27.05.2026 के माध्यम से सूचित किया गया है कि राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वेक्षण के दौरान चिह्नित पाण्डुलिपियों का डिजिटलीकरण और मेटाडेटा निर्माण किया जाना है। इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा एजेन्सी का चयन किया गया है, जिसका दर ₹ 3.34/- (जी0एस0टी0 रहित) प्रति ईमेज निर्धारित किया गया है। इस क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित Specifications के अनुरूप अपने स्तर से एजेंसी का चयन कर डिजिटिजेशन का कार्य कराने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। इस कार्य में किये

गये वास्तविक खर्च का ऊपर उल्लिखित दर की सीमा तक प्रतिपूर्ति डिजिटलीकरण कार्य के संतोषजनक निष्पादन के प्रमाण पत्र, वेन्डर के भुगतान का इनवॉइस एवं वेन्डर को किये गये भुगतान के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जायेगी। बिहार राज्य में राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वे के क्रम में अब तक आठ लाख से अधिक पाण्डुलिपियों को चिह्नित किया जा चुका है। पूरी योजना के दौरान लगभग दस लाख पाण्डुलिपियों में पृष्ठों की अनुमानित संख्या 1,58,24,804 है। भारत सरकार द्वारा चयनित एजेंसी के दर के अनुसार डिजिटलीकरण का अनुमानित लागत ₹ 6,23,68,718/—(छ: करोड़ तेईस लाख अड़सठ हजार सात सौ अठारह रुपये) मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस योजना के लिए मांग संख्या 08 के अंतर्गत नया बजट शीर्ष खोलकर बजट उपबंध कराया जायेगा।
4. प्रस्ताव पर दिनांक 08.07.2026 को सम्पन्न बैठक में लोक वित्त समिति द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।
5. प्रस्ताव पर दिनांक—05.08.2026 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या—03 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
प्रणव कुमार,  
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1003-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>